Credit offered by the World Bank to Indian Railways

*695. SHRI YOGENDRA SHARMA:
SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO:†

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Bank has offered to increase its credit facility to the Indian Railways; and

(b) if so, what are the details thereof and what is Government's reaction thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b) A World Bank Mission is likely to visit India in January, 1978 to undertake appraisal of a new Railway Credit Project which is likely to cover workshop and locomotive modernization and manufacture of wheels and axles etc.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, हमारे रेल मंत्री और रेल मंत्रालय एक मायने में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने मुनाफा कमाया है, मुनाफा कमा रहे हैं । रेलवे मुनाफे में जा रही है और न केवल मुनाफे में जा रही है, बल्कि उसको ऋण भी मिल रहा है और ऋण वर्ल्ड बैंक से मिलने जा रहा है । ऐसी परिस्थिति में बिहार ने क्या पाप किया है कि पचासों वर्षों से जो रेल सेवा उसको उपलब्ध थी, जैसी कि बीफपुर से महादेवपुर घाट रेल सेवा, फतुवा इस्लामपुर रेल सेवा, आरा सहसाराम रेल सेवा, इन तमाम सेवाओं को आप समाप्त कर रहे हैं और तब समाप्त कर रहे हैं जब कि आपकी नयी पार्टी जिसमें बहुत सी पार्टियां हैं जिनका नाम लेने पर आप एतराज करते है, इसलिए हम भूतपूर्व लगाते है, सबसे पहले यह कहते है कि आप अविकसित और ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने जा रहे है । यह तीनों रेल सेवायें अविकसित और ग्रामीण क्षेत्रों में आती हैं । अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं तो आप इन्हें क्यों समाप्त कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मान्यवर, जो सवाल पूछा गया है वह सम्बन्धित नही है । फिर भी इसलिए जवाब देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य को कोई गलतफहमी न रह जाये । आपकी यह गलतफहमी है कि जो वर्ल्ड बैंक की ओर से हम लोगों को सहायता मिलती है वह किस प्रोजेक्ट पर हम खर्च करे इसकी हमे आजादी मिली हुई है । उन्होंने शुरू में जो पालिसी अख्तियार की थी उसके मुताबिक जिन कामों के अन्दर कम्पोनेंट आफ फारेन एक्सचेंज है या फारेन एक्सेंज का ताल्लुक होता है उन योजनाओं पर खर्च करने के लिए वह सहायता हमें मिलती है । परन्तु आपने जिस रेल लाइन का जिक्र किया है ऐसी कई रेल लाइनें हैं, हिन्दुस्तान के अलग अलग प्रान्तों में है । जिस रेल लाइन का आप जिक्र कर रहे है इस सवाल को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां के मजदूरों के साथ जिन्होंने गद्दारी की है उनके कांट्रेक्ट को हम समाप्त कर दें और 30 दिसम्बर के लिए उनको नोटिस भी दे दिया है । मजदूरों के साथ हमने यह भी वायदा किया है कि इन लाइनों पर काम पूरा होने के बाद वहां के पुराने मजदूरों को हम रेल सेवा में ले लेंगे । जहां तक कंस्ट्रक्शन आफ रेलवे लाइन का ताल्लुक है नई रेलवे लाइनों को बनाने के लिए जो खर्च आएगा वह वर्ल्ड बैंक के लोन से नहीं किया जा सकता है । परन्तु हमें इस बात की जानकारी मिली है कि वर्ल्ड बैंक अपनी पालिसी में तबदीली करना चाहता है । जनवरी महीने में उनकी

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Yogendra Sharma.

एक टीम आने वाली है । हम कोशिश करेंगे कि एक नया नक्शा उनके सामने रखें और उनसे इजाजत मांगें। हो सकता है कि उनकी जो पुरानी पालिसी है, उसमें कुछ चेंज हो सके । अगर यह चेंज हो गया तो हमारा रास्ता खुल जाएगा ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, रेल मंत्री महोदय को यह अवसर मिलेगा कि वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों से क्या ऋण लें, किस बात के लिए ऋण ले, किन शर्तों पर ऋण लें, इन सारी चीजों पर बात करने का मौका मिलेगा । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या रेल मंत्री महोदय उस बातचीत के सिलसिले में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पटना में भी रेल पुल का निर्माण हो जिसकी मांग आज समूचा बिहार कर रहा है ?

प्रो० मधु दण्डवते : एक-एक प्रान्त के लिए जो सहायता की आवश्यकता है, वह हम उनके सामने नहीं रखेंगे । जहां तक पटना के पुल का सवाल है उसके बारे में मंत्रालय के स्तर पर हम लोगों को विचार करना होगा, प्लानिंग कमीशन के स्तर पर विचार करना होगा और आपको यह भी बता दूं चाहे वह किसी प्रौजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम हो, प्लानिंग कमीशन की सैंक्शन और क्लीयरेंस लेना आवश्यक है । लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो मदद आएगी अगर उसमें फारेन एक्सचेंज वाली शर्त नहीं रहेगी तो जैसे बंगलौर के नजदीक व्हील एक्सेल प्लांट है, दूसरी तरफ स्टीम लोकोमोटिव मेन्टिनेंस का काम हो रहा है, डीजलाईजेशन हो रहा है, जमालपुर वर्कशाप है, पुरानी रोलिंग मिल बन्द हो गई है, मजदूर शायद बेकार हो सकते हैं तो ऐसी जगह जहां लोकोमोटिव का माडर्नाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग वर्कशाप्स का माडर्नाइजेशन करना है इन सबके लिए वर्ल्ड बैंक के लोन की जरूरत होगी । इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुये कौन सा रुपया कहां लगाना है, विचार किया जाएगा ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : पटना के बारे में क्या कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक के साथ . . .

श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या आप बताने जा रहे है ?

प्रो० मधु दण्डवते : विचार हो रहा है ।

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: Will the Government also consider the Konkan railway connecting ...

MR. CHAIRMAN: The question asked is only about the financial assistance to be taken from the World Bank.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: The question is about the aid from the World Bank. And the Minister has also said that this also would be put to the World Bank for consideration.

MR. CHAIRMAN: True, but for that you have to ask a separate question. Otherwise, how can he collect information from every quarter?

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: Sir, this is an important question.

MR. CHAIRMAN: May be an important question, but you have to ask a separate question.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: At present, we are connecting the North and the South. Sir, we are connecting North with the South. Sir, you should allow if the Minister is willing to reply.

MR. CHAIRMAN: The Minister may reply, but if it is not relevant I am not going to allow the Minister also to reply.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: The Minister is willing to reply....

MR. CHAIRMAN: The Minister knows many things. Mr. Minister, will you reply to this question?

PROF. MADHU DANDAVATE: I will take your permission. I am guided by your advice.

MR. CHAIRMAN: His supplementary has nothing to do with this question. But if you want to reply you may do so.

PROF. MADHU DANDAVATE: For all the prospective expenditure we have to discuss with the World Bank. But we would not be discussing the individual cases. We will only discuss the general norms of the expenditure and then we will take our own decision.

MR. CHAIRMAN: Mr. Gunanand Thakur. Please be brief.

श्री गुणानन्द ठाकुर : वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों या पिछडे देशों को कर्ज देकर उनके विकास में सहयोग देना और सहायता करना है । इन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड बैंक से पालिसी के सम्बन्ध में डिस्कशन करेंगे । इनकी सरकार की नीति है पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना और शायद इनकी भी नीति है पिछड़े क्षेत्रों और लोगों का विकास करना तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह वर्ल्ड बैंक से डिस्कशन करेंगे तो क्या सैद्धान्तिक पहलू पर ऐसे पिछडे क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध मे कर्ज लेंगे जहां पर कि रेल की लाइनें प्राकृतिक कारणों से टूट गयी है या जहां रेल लाइनें बहुत ही आवश्यक है । क्या इन चीजों पर वह वर्ल्ड बैंक से डिस्कशन करेंगे और इस प्रकार जो पैसा मिलेगा, उस पैसे को उन क्षेत्रों में लगायेंगे क्योंकि आज दिक्कत यह हो रही है कि मंत्रालय कहता है कि हम योजना कमीशन से स्वीकृति लेते हैं और योजना कमीशन कहता है कि मंत्रालय हमको स्वीकृति दे, अत: इस सारे चक्कर में सारा सैद्धान्तिक पहलू समाप्त होता जा रहा है । अब मैं सीधा यह सवाल करना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक कितना पैसा देने जा रहा है और उन पैसों को सैद्धान्तिक रूप मे क्या माननीय मंत्री जी उन पिछड़े क्षेत्रों के विकास और रेल लाइनों के रेस्टोरेशन के लिए लगायेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : मान्यवर, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक के साथ हम अपने अन्दरूनी मामलों के बारे मे कुछ चर्चा नही करेंगे । उनके साथ यही चर्चा होगी कि वे हम लोगों को जो असिस्टेंस देंगे उसका जैसा कि पुराना आधार था क्या उसी पर वे हमें फारेन एक्सचेंज कम्पोनेन्ट के लिए सहायता देंगे या हमारे इन्टरनल प्रोजेक्ट के लिए देंगे केवल इतना ही जनरल आधार हम तय करेंगे । उसके बाद के दूसरे फैक्टर्स हम अपने मंत्रालय और प्लानिंग कमीशन के आधार पर देश मे तय करेंगे ।

SHRI S. KUMARAN: May I know from the hon'ble Minister whether the electrification of the Railways including Southern Railways is also included in the World Bank Scheme.

PROF. MADHU DANDAWATE: I have already made it clear just now that only the question of modernisation is before us. As far as the concrete expenditure is concerned, we will spell out our policy.

SHRI S. KUMARAN: The electrification of the Southern Railways is also a part of the modernisation.

PROF. MADHU DANDAVATE: This is an internal problem which we will discuss among ourselves and formulate the policy. I have said in this House umpteen number of times what is our priority as far as the allocation is concerned.